

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

डा० मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 20/2017

श्रीचन्द पुत्र हनुमान जाति मीणा, निवासी मीणा की ढाणी तन गोविन्ददासपुरा, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू

-अपीलाधीन

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू

- रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 23.8.2016
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीचन्द
मु.न. 42/2016, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थिति:-

1. श्री राजेश पुनिया, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट-----रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 16.11.2017

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 28.3.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीचन्द मु.न. 42/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतडी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि-जमीन हाल खसरा नंबर 2779 रकबा 2.46 हेक्टर किरम गैर मुमकिन रद्दा सरहद राजसव ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का तयीदा पर अपीलान्ट द्वारा 320 वर्गमीटर पर तथाकथित रूप से पुख्ता मकान बनाने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने एवं 50 रुपये तावान कायम किये जाने का आदेश पारित



अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

किया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया कि-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलांत का जमीन हाल खसरा नंबर 2779/1909 किस्म गैर मु. रड़ा वाके ग्राम गोविन्दपुरा के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत का अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलांत के मकान पूर्वजों के समय से हैं तथा पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं। जहां अपीलांत के मकान पहले से बने हुये हैं वह जमीन गैर मु. रड़ा की जमीन न होकर आबादी भूमि है। अपीलांत अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है। अपीलान्त के पास अन्य रिहायश के लिए कोई जगह नहीं है। अपीलांत के चारों ओर गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं, जहां विद्युत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये हैं। इस प्रकार अपीलान्त गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल. आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलांत के चारों ओर समाज कल्याण भवन, सरकारी पानी की टंकी, सरकारी विद्यालय आदि भी बने हुये हैं। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न है वहां पर कानून से सदभाविक रूप से काबिज है उसको रिफॉर्म रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही बाद साक्ष्य बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलांत को अतिक्रमी मानने का आधार दर्ज नहीं किया। हल्का पटवारी ने खानन माफिया से मिलकर झूठी रिपोर्ट तैयार की है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.8.20116 खारिज किया जाये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांत



अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलांत का जमीन हाल खसरा नंबर 2779/1909 किस्म गैर मु. रड़ा वाके ग्राम गोविन्दपुरा के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत का अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलांत के मकान पूर्वजों के समय से हैं तथा पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं। जहां अपीलांत के मकान पहले से बने हुये हैं वह जमीन गैर मु. रड़ा की जमीन न होकर आबादी भूमि है। अपीलांत अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है। अपीलान्त के पास अन्य रिहायश के लिए कोई जगह नहीं है। अपीलांत के चारों ओर गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं, जहां विद्युत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये हैं। इस प्रकार अपीलान्त गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल. आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलांत के चारों ओर समाज कल्याण भवन, सरकारी पानी की टंकी, सरकारी विद्यालय आदि भी बने हुये हैं। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न है वहां पर कानून से सदभाविक रूप से काबिज है उसको रिफॉर्म रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही बाद साक्ष्य बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलांत को अतिक्रमी मानने का आधार दर्ज नहीं किया। हल्का पटवारी ने खानन माफिया से मिलकर झूठी रिपोर्ट तैयार की है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.8.20116 खारिज किया जाये।

भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त का अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्त के मकान पूर्वजों के समय से हैं तथा पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं। जहां अपीलान्त के मकान पहले से बने हुये हैं वह जमीन गैर मु. रज़ा की जमीन न होकर आबादी भूमि है। अपीलान्त अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है। अपीलान्त के पास रिहायश के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। अपीलान्त के चारों ओर गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं जहां विद्युत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये हैं। इस सप्रकार अपीलान्त गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्त के चारों ओर समाज कल्याण भवन, सरकारी पानी की टंकी, सरकारी विद्यालय आदि भी बने हुये हैं। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न है वहां पर कानून से सदभाविक रूप से काबिज है उसको सिर्फ रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही बाद साक्ष्य बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय खेतड़ी का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैसाकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारिज की जाये।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। पटवार हल्का त्थीदा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने जमीन हाल खसरा नंबर 2779 रकबा 2.46 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रज़ा सरहद राजस्व ग्राम गोविन्ददासपुरा पर 320 वर्गमीटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं अपील में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैध माना जा सके। ऐसी स्थित में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये तहसीलदार खेतड़ी द्वारा



अति. नि. फिलेक्टर
हनु

पारित निर्णय दिनांक 03.11.2016 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 23.08.2016 मु0 नंबर 42/2016 उनवानी सरकार बनाम श्रीचन्द यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0 आर0 कलेक्टर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
मुजफ्फरपुर

निर्णय दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रा के साथ न्यायालय में सुनाया गया।



(एम0 आर0 कलेक्टर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
मुजफ्फरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

डा० मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 20/2017

श्रीचन्द पुत्र हनुमान जाति मीणा, निवासी मीणा की ढाणी तन गोविन्ददासपुरा, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू

-अपीलाधीन

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू

- रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 23.8.2016
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीचन्द
मु.न. 42/2016, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थिति:-

1. श्री राजेश पुनिया, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट-----रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 16.11.2017

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 28.3.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीचन्द मु.न. 42/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतडी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि-जमीन हाल खसरा नंबर 2779 रकबा 2.46 हेक्टर किरम गैर मुमकिन रद्दा सरहद राजसव ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का तयीदा पर अपीलान्ट द्वारा 320 वर्गमीटर पर तथाकथित रूप से पुख्ता मकान बनाने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने एवं 50 रुपये तावान कायम किये जाने का आदेश पारित



अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू